मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में लेक क्वीन क्रूज का किया उद्घाटन

क्रूज से पर्यटन-रोजगार के अवसर बढ़ेंगे : योगी

संबोधन

गोरखपुर मुख्य संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लैंड लॉक्ड स्टेट कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में सरकार ने नदियों में क्रूज सेवा शुरू करने के लिए इनलैंड वाटर-वे ऑथॉरिटी का गठन किया है। क्रूज सेवा से पर्यटन बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।

मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को रामगढ़झील में क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन करने के बाद जेट्टी पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सड़कों को टू लेन से ट्वेल्व लेन तक बनाया जा रहा है। रेल और एयर कनेक्टिविटी भी शानदार है। सीएम ने कहा कि इसके बावजूद यूपी को लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जाता था। लेकिन पीएम मोदी ने इसका भी रास्ता निकाल दिया है। वाराणसी से हल्दिया तक गंगा नदी में इनलैंड वाटर-वे बनाकर क्रूज चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी बढ़ाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) और पर्यटन विभाग को मिलकर आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

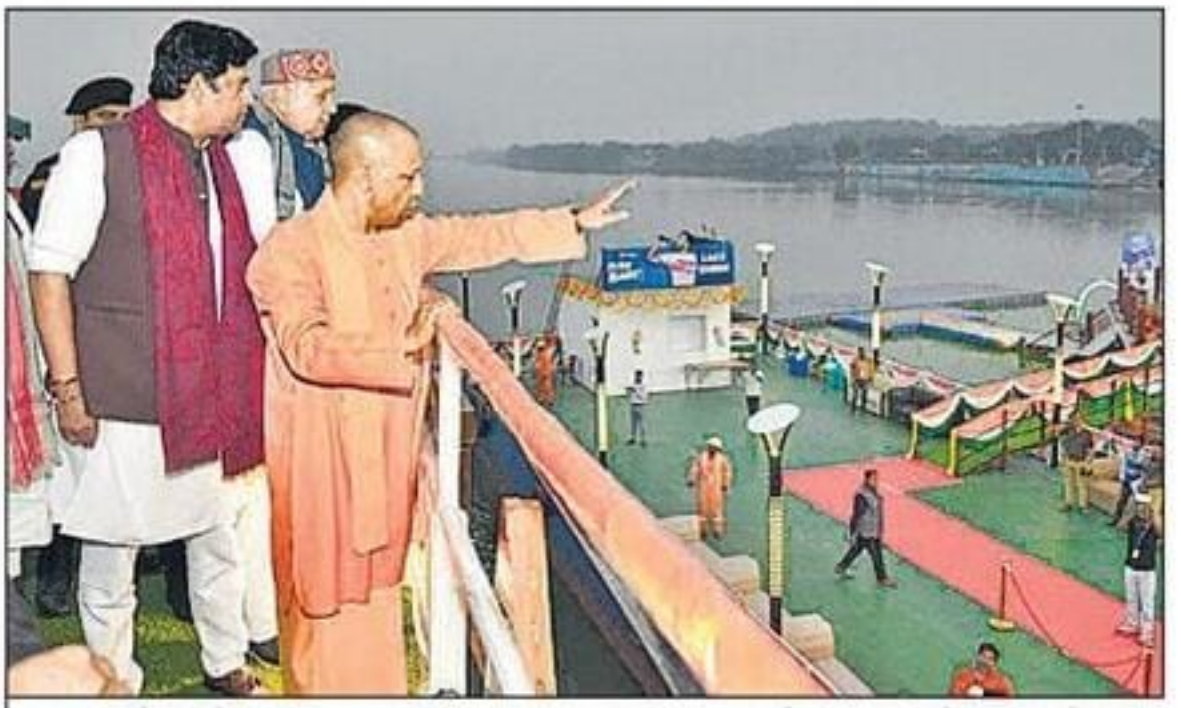

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर की रामगढ़ झील में क्वीन लेक क्रूज का उद्घाटन किया।

खराब प्रदर्शन पर नोटिस देंगे

लखनऊ,विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा 15 से 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर राजस्व वादों के निपटारे की समीक्षा करने के निर्देश दिए है। समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन वाले पांच कमिश्नर और पांच डीएम से जवाब तलब करने के साथ शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके साथ ही खराब प्रदर्शन वाले दस एसडीएम और दस तहसीलदार को स्पष्टीकरण नोटिस थमाया जाएगा। राजस्व सचिव जीएस नवीन ने बताया कि नोटिस के बाद भी कार्य में सुधार न होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

ये करेंगे समीक्षा: विंध्याचल धाम और गोरखपुर मंडल की समीक्षा खुद सीएम करेंगे। लखनऊ मंडल राजस्व सचिव जीएस नवीन, कानपुर, झांसी मंडल विशेष सचिव राजस्व अनुराग पटेल और बरेली, देवीपाटन मंडल विशेष सचिव राजस्व राम केवल करेंगे। इसी तरह वाराणसी, प्रयागराज एवं आजमगढ़ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त टीके शिबु और आगरा, अलीगढ़ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव करेंगे।